आर. कोलांडाइवेलु व अन्य

बनाम

सरकार तमिलनाडु व एएनआर के.

(सिविल अपील संख्या 8235/2009)

11 दिसम्बर, 2009

(तरूण चटर्जी और सुरिंदर सिंह निज्जर, जे.जे.)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894;

धारा 11ए-उद्देश्य और विधायी आशय- चर्चा की गई।

धारा 11ए अनुदान सीमा- भूमि अधिग्रहण कार्यवाही-धारा 6 घोषणा 23.12.1987 को जारी-भूमि मालिकों द्वारा रिट याचिका-अंतरिम आदेश-11.2.1988-को चार सप्ताह के लिए रोक- 3.7.1991 को बेदखली पर रोक का आदेश- पंचाट पारित 23.8.1993 को- रिट याचिका अंततः इस आधार पर अपील खारिज कर दी गई कि धारा 6 घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की समाप्ति के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई, माना गयाः अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त नहीं हुई और अनुदान समय के भीतर दिया गया- दो साल से घोषणा की तारीख की गणना उस अवधि को छोडकर की जानी है जब पार्टियों ने अदालत से संपर्क किया और ऐसे अधिग्रहण नोटिस पर अंतरिम रोक प्राप्त की-दोनो पक्ष इस आधार पर आगे

बढे कि शुरू में चार सप्ताह के लिए पारित रोक का अंतरिम आदेश अंतिम आदेश तक जारी रहा। स्थगन के अंतरिम आदेश को हटाने के आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन पारित किया गया।

अपीलकर्ता अधिग्रहरण के तहत भूमि के मालिक थे। उन्होने उच्च न्यायालय के समक्ष 23 दिसंबर 1987 को जारी भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 और धारा 6 घोषणा के तहत अधिसूचना की वैधता पर सवाल उठाते हुए रिट याचिकाएं दायर की। लंबित रिट याचिकाओं में अंतरिम आदेश दिनांक 11 फरवरी 1988 द्वारा रोक लगा दी गई,

एक सप्ताह का समय दिया गया। राज्य-प्रतिवादी ने स्थगन आदेश को हटाने के लिए आवेदन दायर किया। 3 जुलाई 1991 को बेदखली पर रोक का आदेश पारित किया गया। यह पुरस्कार 23 अगस्त 1993 को पारित किया गया। रिट याचिकाएं अंततः खारिज कर दी गई।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि रोक का अंतरिम आदेश 11 फरवरी, 1988 से 11 मार्च, 1988 तक केवल चार सप्ताह की अवधि के लिए प्रभावी था, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को खारिज करने में गलती की। 23 अगस्त 1993 को पारित पुरस्कार 23 दिसंबर 1997 को धारा 6 के तहत घोषणा जारी करने की तारीख से स्पष्ट रूप से दो साल की अवधि से परे थी।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित कियाः

प्रासंगिक प्रावधान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1394 अर्थात् धारा 6 और 11 ए का अवलोकन किया गया। इसके स्पष्टीकरण से पता चलता है कि तारीख से दो साल घोषणा की गणना उस अवधि को छोडकर की जानी चाहिए जब पार्टियों ने अदालत से संपर्क किया था और ऐसे अधिग्रहरण नोटिस पर अंतरिम रोक प्राप्त की थी। अपीलकर्ताओं के कहने पर, अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना और धारा 6 के तहत घोषणा पर शुरूआत में 11 फरवरी, 1988 को चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई थी, लेकिन अंतवर्ती आवेदन बने रहे। अंतिम निपटान के लिए लंबित और अंततः राज्य / उत्तरदाताओं के कहने पर स्थगन आदेश को हटाने के आवेदनों पर, स्थगन को हटाने के आवेदनों को एक आदेश द्वारा निपटाया गया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि शुरू में चार सप्ताह के लिए दिया गया स्थगन आदेश होगा, अगले आदेश तक जारी रखें। उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि अगले आदेश तक अपीलकर्ताओं को अर्जित भूमि-से बेदखल करने पर रोक का आदेश पारित किया गया था। (पैरा 7 और 10) (389-जी-एच; 390-ए-8; 391-जी-एच)

1.2 स्थगन के अंतरिम आदेश की प्रकृति पर विचार करते हुए अंततः 3 जुलाई, 1991 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित, यह पूरी तरह से सपष्ट है कि दोनो पक्ष इस आधार पर आगे बढे कि स्थगन का अंतरिम आदेश जारी था और उत्तरदाताओं को अगले आदेशों तक अपीकर्ताओं को

अधिग्रहित भूमि से बेदखल करने से रोक दिया गया था। यदि ऐसा मामला नहीं होता, तो अपीलकर्ताओं के पक्ष में दिए गए स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने का सवाल ही नहीं उठता और अपीलकर्ताओं के पास इस आधार पर स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन का विरोध करने का कोई अवसर नहीं था कि रोक का अंतरिम आदेश जारी था और इसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा यह कहा जा सकता है कि हालांकि शुरू में अंतरिम आदेश चार सप्ताह के लिए पारित किया गया था, वहीं अंतरिम आदेश जो शुरू में दिया गया था उसे 3 जुलाई, 1991 को अगले आदेश तक अंतिम बना दिया गया था। तथ्यों के उपरोक्त विवरण से, यह होना चाहिए यह माना गया कि अंतरिम आदेश देने के लिए लंबित आवेदनों और अगले आदेशों तक दिए गए अंतरिम आदेश के मद्देनजर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि अधिग्रहीत भूमि से संबंधित अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई थी। (पैरा 11) (391-जी-एच; 392-ए-सी)

2. अधिनियम की धारा 11ए की व्याख्या का उद्देश्य भूमि धारक को लाभ प्रदान करना है, जिसकी भूमि धारा 6 के तहत घोषणा के बाद अधिगृहित की जाती है। धारा 11ए के प्रावधान के अनुसार, राज्य प्राधिकारियों को अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की

तारीख से दो साल के भीतर अंतिम पुरस्कार पारित करना आवश्यक है, ऐसा न करने पर अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, और यह स्पष्ट रूप से इरादे को दिखाएगा विधायिका ने कहा कि इस प्रावधान का लाभ भूमि मालिक के पक्ष में होगा यदि घोषणा की तारीख से दो साल के भीतर कोई आदेश प्राप्त नहीं होने पर कोई अवार्ड पारित नहीं किया जा सका। न्यायालय द्वारा भूमि स्वामी के अधिग्रहण पर रोक लगाने और अधिनियम की धारा 11ए के अर्थ के अंतर्गत घोषणा या अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के कारण भूमि ,भूमि स्वामी को वापस कर दी जाएगी। (पैरा 13)(393-सी-एफ)

3. मामले का एक और पहलू भी है, जिस उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन किया गया था और धारा 11 ए अधिनियमित किया गया था, वह भूमि अधिग्रहरण अधिका द्वारा अनुदान देने में होने वाली अत्यधिक देरी को रोकना था, जो भूमि मालिकों को उनकी भूमि के आनंद से वंचित कर देता था या उस भूमि से निपटता था जिसका कब्जा था पहले ही ले लिया गया था, अनुदान देने में देरी के कारण भूमि के मालिक को अनगिनत कठिनाईयों का सामना करना पडा। अधिनियम में धारा 11ए को शामिल करने के उद्देश्य और कारण यह थे कि '' अधिग्रहरण की कार्यवाही लंबे समय तक लंबित रहने से अक्सर प्रभावित पक्षों को कठिनाई होती है और उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे का पैमाना अवास्तविक हो जाता है' और ''एक अवधि प्रदान करने का प्रस्ताव

है अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि के भीतर कलेक्टर को अधिनियम के तहत अपना अनुदान देना चाहिए। इस स्पष्टीकरण और अधिनियम की धारा 11ए की शुरूआत के द्वारा, विधान मंडल का इरादा इस बात पर जोर देना था कि कलेक्टर अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल के भीतर अधिनियम के तहत अपना अनुदान देगा, अन्यथा अधिग्रहण नहीं होगा। कार्यवाही स्वयं समाप्त हो जाएगी। (पैरा 15)(394-सी-एफ)

4. अपीलकर्ताओं ने रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का लाभ उठाया था, जिसे राज्य/उत्तरदाताओं ने स्थगन आदेश को हटाने के लिए एक आवेदन दायर करके रद्द करने की मांग की थी, निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि अनुदान अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल के भीतर पारित किया गया। उत्तरदाता इस अवधि को उपवर्जित करवाने के हकदार थे।

11 फरवरी, 1988 से 3 जुलाई, 1991 तक और, इसलिए, यदि इस अवधि को अधिनियम की धारा 11ए के स्पष्टीकरण में निहित के रूप में बाहर रखा गया है, तो अनुदान समय के भीतर था और इसलिए, यह मानने का प्रश्न है कि अधिग्रहण की कार्यवाही होनी चाहिए उक्त अवधि की

समाप्ति के कारण चूक उत्पन्न ही नहीं हो सकती। (पैरा 17) (396-एच; 397-ए-सी)

अशोक कुमार एवं अन्य। हरियाणा राज्य और अन्य 2007 (3) एससीसी 470, प्रतिष्ठित.....

बैलम्मा (श्रीमती) अलियास डोड्डाबेलम्मा और अन्य बनाम पूर्णप्रजना हाउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य 2006 (2) एस सी सी 416 और युसुफबहाल नूरमोहम्मद नेंदोलिया बनाम गुजरात राज्य और अन्य 1991 (4) एससीसी 531, पर भरोसा किया गया।

केस कानून संदर्भ

2007(3) एससीसी 470	विशिष्ट	5 के लिए
2006(2) एससीसी 416	पर भरोसा	6 के लिए
1991(4) एससीसी 531	पर भरोसा	6 के लिए

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या. 2009 का 3235

उच्च के निर्णय एवं आदेश दिनांक 23।01.2007 से 2001 की रिट अपील संख्या 1735 में मद्रास न्यायालय।

वी. कृष्णमूर्ति, आर. विटुथलाई, प्रशांत पी., प्राची बाजपेश्ी, के.वी. उपस्थित पक्षों के लिए भारती उपाध्याय, आर. नेदुमारन, प्रोमिला, जगदीश, इंदिरा, एस. थानंजयन।

न्यायालय द्वारा न्यायामूर्ति तरूण चटर्जी, जे. ने निर्णय पारित किया गया

1. -स्वीकृति दी गई

2. अपीलकर्ता तमिलनाडु के सलेम जिले में सलेम तालुका संख्या 151, अयोथियापट्टम में स्थित भूमि के मालिक हैं (इसके बाद इसे अधिगृहीत ''भूमि'' के रूप में जाना जाएगा)।

उक्त भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में ''अधिनियम'') की धारा 4(1) के तहत 24 दिसंबर, 1986 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। अधिनियम की धारा 6 के तहत एक घोषणा 23 दिसंबर, 1987 को जारी की गई थी। 1988 की डब्ल्यू.पी.एनओएस. 835 और 836 नामक दो रिट याचिकाएं मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष पूर्वोक्त अधिसूचना और घोषणा की वैधता और वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए दायर की गई थी। लंबित रिट याचिकाओं में 11 फरवरी, 1989 को निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया गयाः-

''चार सप्ताह के लिए अंतरिम रोक। नोटिस चार सप्ताह में वापस किया जा सकता है''

उपरोक्त दो रिट याचिकाएं अंततः उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश के समक्ष सुनवाई कि लिए आई, जिन्होनें 23 अगस्त, 2001 के एक

आदेश द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया और अपीलार्थी ने व्यथित महसूस करते हुए, डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की, जिसने आक्षेपित आदेश दिया। अपीकर्ताओं की अपील खारिज कर दी थी। अपीलकर्ताओं ने व्यथित महसूस करते हुए, दो विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की थीं, जिन पर छुट्टी दिए जाने पर, ई पार्टियों के विद्वान वकील की उपस्थिति में सुनवाई की गई थी।

पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुनने के बाद और अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, हमारा विचार है कि इन अपीलों में कोई बल नहीं है। अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कृष्णमूर्ति की दलील थी इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि रोक का अंतरिम आदेश 11 फरवरी, 1988 से 11 मार्च, 1988 तक केवल चार सप्ताह की अवधि के लिए प्रभावी था, उच्च न्यायालय ने दायर रिट याचिकाओं को खारिज करने में एक गंभीर त्रुटि की थी। अपीलकर्ताओं का कहना है कि 23 अगस्त, 1993 को पारित पुरस्कार स्पष्ट रूप से जारी होने की तारिख से दो साल की अवधि से परे था। 23 दिसंबर को अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा।1987, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विदुथलाई ने श्री कृष्णमूर्ति द्वारा दी गई दलीलों का विरोध किया।

अपीलकर्ता ने प्रस्तुत किया कि लंबित रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के अंतरिम आदेश की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं को खारिज करना पूरी तरह से उचित था और इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि इसे धारण करने का प्रश्न संपूर्ण कार्यवाही समाप्त हो गई थी और अधिग्रहीत भूमि अपीलकर्ताओं को वापस लौटाई जानी चाहिए, इसका सवाल ही नहीं उठता। इससे पहले कि हम हमारे सामने रखे गए मुद्दे पर विचार पर विचार करे, अधिनियम के कुछ प्रावधानों से निपटना आवश्यक होगा। ऐसे प्रावधानों में से पहला है कि अधिनियम की धारा 6 जो इच्छित अधिग्रहण से संबंधित है। अधिनियम की धारा 6 के स्पष्टीकरण मे कहा गया है कि '' पहले प्रावधान में निर्दिष्ट किसी भी अवधि की गणना करने में, वह अवधि जिसके दौरान धारा 4 (1) के तहत जारी अधिसूचना के अनुसरण में की जाने वाली कोई भी कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक लगा दी जाती है। किसी न्यायालय के आदेश से बाहर रखा जाएगा।''

3. अधिनियम की धारा 11 कलेक्टर द्वारा जांच और अनुदान संबंधित है। इससे लगता है- ''इस प्रकार निर्धारित दिन पर, या किसी अन्य दिन जिस पर जांच स्थगित कर दी गई है, कलेक्टर उन आपत्तियों (यदि कोई हो) की जांच करने के लिए आगे बढेगा, जो किसी भी इच्छुक व्यक्ति ने धारा 9 के तहत दिए गए माप के नोटिस के अनुसार बताई है, धारा 8 के तहत और भूमि के मुल्य में और

धारा 4 उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि पर और मुआवजे का दावा करने वाले व्यक्तियों के संबंधित हितों में और अपने हाथ से अनुदान देगा.

4. इसके बाद इस मामले के प्रयोजन के लिए अधनियम का सबसे प्रासंगिक प्रावधान आता है यानी अधिनियम की धारा 11ए जो उस अवधि से संबंधित है, जिसके भीतर एक अनुदान दिया जाएगा, यह कहता है कि ''कलेक्टर धारा 11 के तहत अनुदान देगा घोषणा के प्रकाशन की तारिख से दो माह की अवधि में कोई अनुदान नही दिया जाता है तो भुमि अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो जाएगीं। बशर्ते कि ऐसे मामले में जहा उक्त घोषणा की गई हो।

भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 (1984 का 68) के प्रारंभ होने से पहले प्रकाशित, यह अनुदान ऐसे प्रारंभ होने से दो वर्ष की अवधि के भीतर दिया जाएगा। इस खंड में निर्दिष्ट दो वर्षो की अवधि की गणना में स्पष्टीकरण, वह अवधि जिसके दौरान उक्त घोषणा के अनुसरण में की जाने वाली कोई कार्यवाही या कार्यवाही न्यायालय के आदेश द्वारा रोक दी जाती है, को बाहर रखा जाएगा।

5. जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री वी. कृष्णमूर्ति ने आग्रह किया कि इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुए कि दो रिट याचिकाओं में उच्च

न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के सीमित आदेश को आगे नहीं बढाया गया था। यह, जो पुरस्कार पारित किया गया था वह घोषणा के प्रकाशन की तारिख से दो साल की अवधि की समाप्ति के बाद समाप्त हो गया था, इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि अधिग्रहित भूमि के अधिग्रहण की पूरी कार्यवाही समाप्त हो गई थी और, तदनुसार, अपीलकर्ताओं की श्री कृष्णमूर्ति ने हमारा ध्यान इस स्वीकृत तथ्य की ओर आकर्षित किया था कि अधिनियम की धारा 6 के तहत अधिसूचना 23 दिसंबर, 1987 को अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन का सिमित अंतरिम आदेश दिया गया था। 11 फरवरी 1988 और 3 जुलाई 1991 को अपीलकर्ताओं के पक्ष मे बेदखली पर रोक का आदेश पारित किया गया और उसके बाद अंततः 23 अगस्त 1993 को पुरस्कार पारित किया गया। उपरोक्त तथ्यों से, श्री कृष्णमूर्ति के अनुसार, यह स्पष्ट होगा कि एफ ने अधिनिमय की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारिख से दो वर्ष की अवधि को स्वीकार किया है। 23 दिसंबर 1987 पुरस्कार की तारिख से पहले यानी 23 अगस्त, 1993 को समाप्त हो गई थी, हालांकि चार सप्ताह के लिए रोक का एक सिमित आदेश दिया गया था जिसे विचार के लिए किसी भी आदेश द्वारा बढाया नहीं गया था। इस तर्क के समर्थन में, श्री कृष्णमूर्ति ने अशोक कुमार और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर मजबूत

भरोसा जताया। बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2007 (3) एससीसी 470.

6 .जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है कि उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विदुथलाई ने प्रस्तुत किया। स्थगन आदेश देने के प्रश्न पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन पर, यह स्पष्ट होगा कि सभी पक्ष इस आधार पर आगे बढे थे कि सीमित अवधि के लिए दिया गया स्थगन का अंतरिम आदेश तब तक जारी रहा था वह चरण जब रोक के अंतरिम आदेश को समान शर्तो पर पूर्ण बना दिया गया और आगे उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए कि दोनो पक्ष इस आधार पर आगे बढे कि रोक का अंतरिम आदेश पूरे समय जारी था, यह माना जाना चाहिए कि वह समय जिसके दौरान स्थगन का अंतरिम आदेश जारी था अर्थात 11 फरवरी 1988 से 3 जुलाई 1991 तक को अधिनियम की धारा 11ए के स्पष्टीकरण के अर्थ में अवधि की गणना से बाहर रखा जाना चाहिए और यदि इस समय को बाहर रखा गया है, 23 अगस्त, 1993 को जो पुरस्कार पारित किया गया था, वह समय के भीतर था और इसलिए, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष निकालना पूरी तरह से उचित था कि चूंकि पुरस्कार घोषणा की तारीख से 2 साल की अवधि से परे पारित किया गया था, इसलिए यह मानने का सवाल पूरी तरह से उचित था। संपूर्ण अधिग्रहण कार्यवाही को समाप्त मान लिया जाना चाहिए, ऐसा प्रश्न हीं नहीं उठता। इस प्रस्तुतीकरण के समर्थन

में, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने इस न्यायालय के दो निर्णयों पर भरोसा किया है, बैलम्मा (श्रीमती) अलियास डोड्डाबेलम्मा और अन्य बनाम पूमप्रज्ञा आउस बिल्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य 2006 (2) एससीसी 416 और सूसुफभाई नूरमोहम्मद नंदोलिया बनाम गुजरात राज्य और दूसरा 1991 (4) एस सी सी 531। तदनुसार उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री विदुथलाई ने प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय के आदेशों में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है कि उत्तरदाता अधिनियम की धारा 11ए के स्पष्टीकरण के संदर्भ में अवधि को बाहर करने के हकदार थे।

7. हमने पक्षों के विद्वान वरिष्ठ वकील की प्रतिद्वंद्वी दलीलों की सावधानीपूर्वक जांच की है। हमने उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश के साथ साथ अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान अर्थात् धारा 6 और 11ए की व्याख्या के साथ भी जांच की है, जैसा कि यहां पहले बताया गया है। उपरोक्त प्रावधानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होगा कि घोषणा की तारीख से दो वर्षो की गणना को छोडकर की जानी चाहिए।

वह अवधि जब पार्टियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और ऐसे अधिग्रहण नोटिसों पर अंतरिम रोक लगा दी थी जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, रिट याचिकाओं के प्रवेश के समय, 11 फरवरी 1988 को निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया गया था-

''चार सप्ताह के लिए अंतरिम रोक। नोटिस चार सप्ताह में वापस किया जा सकता ह'

8. इस अंतरिम आदेश के पारित होने के बाद यह सच है कि अंतरिम आदेश को न्यायालय के किसी भी अगले आदेश द्वारा विस्तारित नहीं किया गया था, हालांकि पार्टियों ने सोचा कि अंतरिम आदेश जारी था। इसे ध्यान में रखते हुए, राज्य/प्रतिवादियों ने न्यायालय द्वारा दिए गए 11 फरवरी, 1988 के अंतरिम आदेश को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया।

9. 3 जुलाई, 1991 को, राज्य/प्रतिवादियों के कहने पर दायर अंतरिम आदेश को खाली करने के लिए उक्त आवेदन पर, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया

''उच्च न्यायालय की फाईल पर डब्ल्यू, पी. संख्या 835 और 836/88 के समर्थन में दायर याचिकाओं और संबंधित हलफनामों और इस न्यायालय के दिनांक 11.02.88 के आदेश और डब्ल्यू.एम.पी.संख्या में दिए गए हलफनामों पर गौर करने पर ये याचिकाएं गर्म हो गई। 1988 के 1246 और 1249 और यहां दायर जवाबी हलफनामें और डब्ल्यू.एम.पी. संख्या 1248 और 1249/88 में याचिकाकर्ताओं के लिए वकील और डब्ल्यू.एम.पी. संख्या 11986 और 11986 और 11987 में

याचिकाकर्ताओं के लिए यह आदेश दिया गया है कि बेदखल किया जाए,याचिकाकर्ताओं (डब्ल्यू.एम.पी. संख्या 1248 और 1249/90 में) अकेले उनकी भूमि (1) सर्वेक्षण संख्या 99/3ए, अयोथिपट्टम गांव की 1.34 एकड की सीमा। सलेम तालुक, सलेम जिला (डब्ल्यू.एम.पी. संख्या 1248 में 88) और (2) धारा 4(1) के अनुसार क्रमशः डब्ल्यू.एम.पी. संख्या 1248 में सर्वेक्षण संख्या 98/3 और 98/4 अयोथियापट्टम गांव, सेलम जिले में 1-37 एकड दोनों याचिकाओं में प्रथम प्रतिवादी की फाइल पर जी.ओ. सुश्री संख्या 3320 समाज कल्याण, दिनांक 24.12.1986 में अधिसूचना, और तमिलनाडू सरकार राजपत्र अंक संख्या के भाग-2 खंड-2 अनुपूरक के पृष्ठ 21 पर प्रकाशित हुई। 1 सी, दिनांक 07.01.1987, और जी.ओ.एन.एस. में धारा-6 घोषणा। क्रमांक 2532, समाज कल्याण, दिनांक 08.12.1987, और तमिलनाडु सरकार के भाग-2 खंड 2 अनुपूरक के पृष्ठ 23 और 24 पर प्रकाशित। राजपत्र अंक संख्या 49-सी, दिनांक 23.12.1987, जहां तक वे प्रत्येक याचिका में याचिकाकर्ताओं की भूमि से संबंधित है और इसके द्वारा यह याचिका पर अगले आदेशों तक रोक लगाई जाती है।" (जोर दिया गया)

10. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, अपीकर्ताओं के कहने पर, अधिनियम की धारा 4 के तहत जारी अधिसूचना और धारा 6 के

तहत घोषणा पर शुरूआत में 11 फरवरी, 1988 को चार सप्ताह के लिए रोक लगा दी गई थी, लेकिन इंटरलोक्यूटरी आवेदन लंबित रहे। अंतिम निपटान के लिए और अंततः राज्य/प्रतिवादियों के कहने पर स्थगन आदेश को हटाने के आवेदनों पर, स्थगन को खाली करने के आवेदनों का निपटारा किया गया, जैसा कि यहां पहले एक आदेश द्वारा उल्लेख किया गया है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रारंभ में स्थगन आदेश दिया गया था अगले आदेश लंबित रहने तक चार सप्ताह जारी रहेंगे। 3 जुलाई को पारित उच्च न्यायालय के उक्त अंतरिम आदेश के अवलोकन से। 1991, इसलिए, यह स्पष्ट है कि अगले आदेश तक अपीलकर्ताओं को अधिग्रहित भूमि से बेदखल करने पर रोक का आदेश था।

11. यहां उपर की गई हमारी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए और अंततः 3 जुलाई, 1991 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम रोक आदेश की प्रकृति पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि दोनो पक्ष इस आधार पर आगे बढे कि अंतरिम रोक आदेश जारी था और उत्तरदाताओं को अगले आदेशों तक अपीलकर्ताओं को अधिग्रहित भूमि से बेदखल करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। यदि ऐसा नहीं होता, तो अपीलकर्ताओं के पक्ष में दिए गए स्थगन आदेश को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने का सवाल ही नहीं उठता और अपीलकर्ताओं के पास इस आधार पर स्थगन आदेश को

हटाने के लिए आवेदन का विरोध करने का कोई अवसर नहीं था कि स्थगन का अंतरिम आदेश जारी था और इसे जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा, यह कहा जा सकता है कि हालांकि शुरू में अंतरिम आदेश चार सप्ताह के लिए पारित किया गया था, वहीं अंतरिम आदेश जो शुरू में दिया गया था, उसे 3 जुलाई को अगले आदेश तक अंतिम बना दिया गया था। 1991 तथ्यों के उपरोक्त वर्णन से, यह माना जाना चाहिए कि अंतरिम आदेश देने के लिए लंबित आवेदनों और अगले आदेशों के लंबित रहने तक अंतरिम आदेश दिए जाने के मद्देनजर कोई कदम नहीं उठाया जा सकता है। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि अधिग्रहीत भूमि से संबंधित अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की समाप्ति के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो गई थी।

12. यूसुफभाई नूरमोहम्मद के मामले (सुप्रा) में पैरा 8, डी में इस न्यायालय ने निम्नानुसार देखाः-

"उक्त स्पष्टीकरण व्यापक संभव शर्तों में है और, हमारी राय में, उक्त अधिनियम की धारा 11 के तहत पुरस्कार देने से पहले की कार्रवाई या कार्यवाही के लिए स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कार्रवाई या कार्यवाही को सीमित करने का कोई वांरट नहीं है। पहला स्थान, जैसा कि स्वयं विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा रखा गया है, जहां मामला धारा 17 के अंतर्गत आता है,

निर्णय दिए जाने से पहले कब्जा लिया जा सकता है और हमें कोई कारण नहीं दिखता कि स्पष्टीकरण में पूर्वोक्त अभिव्यक्ति को अलग-अलग अर्थ क्यों दिया जाना चाहिए इस पर कि क्या मामला धारा 17 के अंतर्गत आता है या अन्यथा। दूसरी ओर, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 11-ए का उद्देश्य उस भूमि धारक को दिए जाने वाले लाभ को सीमित करना है जिसकी भूमि धारा 6 के तहत घोषणा के बाद अर्जित की गई है। स्पष्टीकरण में शामिल मामले। लाभ यह है कि पुरस्कार घोषणा के दो साल की अवधि के भीतर दिया जाना चाहिए, अन्यथा अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी और भूमि भूमि-धारक को वापस कर दी जाएगी। उक्त प्रावधान का लाभ पाने केलिए क्या है। आवश्यक है, कि भूमि-धारक जो लाभ चाहता है, उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के अनुसरण में किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए अदालत से कोई आदेश प्राप्त नहीं किया होगा ताकि स्पष्टीकरण केवल उन भूमि के मामलों को कवर करे- जिन धाराकों को अदालत से ऐसा कोई आदेश प्राप्त नहीं होता है जिससे पुरस्कार देने या अधिग्रहीत भूमि पर कब्जा लेने में देरी हो गया उसे रोका जा सके।

(जोर दिया गया)

13. इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों से, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 11ए के स्पष्टीकरण का उद्देश्य भूमि धारक को लाभ

प्रदान करना है, जिसकी भूमि धारा 6 के तहत घोषणा के बाद अधिग्रहित की जाती है। धारा 11ए के प्रावधान के अनुसार, राज्य प्राधिकारियों को अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल के भीतर एक अंतिम पुरस्कार पारित करना आवश्यक है, जिसके गिरने पर, अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जाएगी, और यह स्पष्ट रूप से इरादे को दिखाएगा विधायिका ने कहा कि इस प्रावधान का लाभ भूमि मालिक के पक्ष में होगा यदि घोषणा की तारीख से दो साल के भीतर पुरस्कार पारित नहीं किया जा सका, जब भूमि मालिक द्वारा अधिग्रहण पर रोक लगाने के लिए न्यायालय से कोई आदेश प्राप्त नहीं किया गया और भूमि जब्त कर ली गई। अधिनियम की धारा 11ए के अर्थ के तहत घोषणा या अधिसूचना की तारीख से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के कारण भूमि मालिक को वापस कर दिया जाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, प्रारंभ में अधिसूचनाओं पर चार सप्ताह के लिए रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया गया था, लेकिन रिकॉर्ड और दोनों पक्षों के आचरण से और इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि राज्य/प्रतिवादियों को स्थगन आदेश को हटाने के लिए एक आवेदन दायर करना था। यह सोचते हुए कि स्थगन आदेश जारी था और अपीलकर्ताओं ने उसके निपटान तक स्थगन के लिए उक्त आवेदन का विरोध किया था, हमारे मन में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि दोनो पक्ष इस आधार पर आगे बढे कि स्थगन का अंतरिम आदेश शुरू में चार सप्ताह के लिए पारित किया गया था। अंतरिम आदेश को रद्द करने के

आवेदन पर उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम रोक ठहरने के अंतिम आदेश तक जारी रहेगा।

14. हमारे द्वारा अपनाए गए रूख के अनुसार, हमारा मानना है कि पुरस्कार अधिनियम की धारा 11ए के अनुसार पारित किया गया था, यानी, प्रकाशन की तारीख से दो साल के भीतर पुरस्कार पारित किया गया था। अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा।

15. मामले का एक और पहलू भी है, जिस उद्देश्य के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन किया गया था और धारा 11 ए अधिनियमित किया गया था, वह भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा एक पुरस्कार देने में होने वाली अत्यधिक देरी को रोकना था, जो भूमि मालिकों को उनकी भूमि के आनंद से वंचित कर देता था या उस भूमि का निपटान करता था जिसका कब्जा पहले ही ले लिया गया था, पुरस्कार देने में देरी के कारण भूमि के मालिक को अनगिनत कठिनाईयों का सामना करना पडा। अधिनियम में धारा 11 ए को शामिल करने के उद्देश्य और कारण यह थे कि ''अधिग्रहण की कार्यवाही लंबे समय तक लंबित रहने से अक्सर प्रभावित पक्षों को कठिनाई होती है और उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे का पैमाना अवास्तविक हो जाता है' और इसके लिए प्रावधान करने का प्रस्ताव है, अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि जिसके भीतर कलेक्टर को अधिनियम के तहत अपना

पुरस्कार देना चाहिए। इस स्पष्टीकरण और अधिनियम की धारा 11 ए की शुरूआत से, विधान मंडल का इरादा इस बात पर जोर देना था कि कलेक्टर अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल के भीतर अधिनियम के तहत अपना पुरस्कार देगा, अन्यथा अधिग्रहण की कार्यवाही जारी रहेगी। स्वयं समाप्त हो जाएगा, इस संबंध में, बैलम्मा (सुप्रा) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया जा सकता है जैसा कि यहां पहले उल्लेख किया गया है। इस निर्णय में, इस न्यायालय ने ई स्पष्टीकरण के साथ धारा 11ए को पेश करने वाले अधनियम के संशोधन के प्रभाव पर विचार किया गया था और इस संबंध में निम्नानुसार टिप्पणी की गई।

"इस न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दिया कि धारा 11ए को भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा अनुदान देने में की जाने वाली अत्यधिक देरी को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था, जो मालिकों को सम्पत्ति के आनंद से वंचित करता है या उस भूमि को निपटने के लिए किसका कब्जा पहले ही हो चुका है।पुरस्कार देने में देरी के कारण भूमि के मालिक को अनगिनत कठिनाईयों का सामना करना पडा। अधिनियम में धारा 11ए को शामिल करने के उद्देश्य और कारण यह थे कि अधिग्रहरण की कार्यवाही लंबे समय तक लंबित रहने से अक्सर प्रभावित पक्षों को कठिनाई होती है और उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे का पैमाना अवास्तविक हो जाता है और इसके लिए प्रावधान करना प्रस्तावित हैं' अधिनियम की धारा 6 के तहत

घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल की अवधि जिसके भीतर कलेक्टर को अधिनियम के तहत अपना पुरस्कार देना चाहिए। इसलिए, कलेक्टर द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपना पुरस्कार देने पर जोर दिया गया। विधायिका भ्ज्ञी स्थिति की वास्तविकता से अवगत थी और इस तथ्य से अनभिज्ञ नहीं थी कि कई मामलों में इच्छुक पक्षों द्वारा कानून की अदालतों से प्राप्त स्थगन आदेशो के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही रूकी हुई थी। इसलिए, यह जरूरी हो गया कि अवधि की गणना की जाए दो साल की, वह अवधि जिसके दौरान स्थगन आदेश लागू हुआ, जिसने अधिकारियों को घोषणा के अनुसरण में कोई कार्रवाई करने या आगे बढने से रोका, को बाहर रखा जाना चाहिए। यदि ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था, तो स्थगन आदेश प्राप्त करके और उसके बाद मुकदमेंबाजी को लम्बा खींचकर अधिग्रहण की कार्यवाही को आसानी से विफल किया जा सकता है। धारा 11ए का स्पष्टीकरण इस प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए था। स्पष्टीकरण यथासंभव व्यापक शब्दों में है जो इसके संचालन को उन मामलों तक सीमित नहीं करता है जहां अकेले भूमि-मालिक द्वारा स्थगन आदेश प्राप्त किया जाता है। ऐसे मामलों की कल्पना की जा सकती है जहां भूमि मालिकों के अलावा अन्य लोग भी भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही को रोकने में रूचि रखते हो। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अधिकांश रिपोर्ट किए गए निर्णयों में जिस पक्ष ने हत्या का आदेश प्राप्त किया था, यह अधिग्रहित भूमि का मालिक था। लेकिन इससे हम इस

निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे कि स्पष्टीकरण केवल उन मामलों पर लागू होता है जहां भूमि के मालिकों द्वारा स्थगन प्राप्त किया गया था। ऐसे अन्य लोग भी हो सकते है जो अधिग्रहण की कार्यवाही से व्यथित होकर स्थगन आदेश प्राप्त करने में रूचि रखते हो। हो सकता है कि उस क्षेत्र के विकास के कारण आसपास में कुछ लोग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो, या यह किसी अन्य कारण से हो सकता है कि जिस परियोजना के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है, उसने इलाके के लोग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हों। ऐसे कई उदाहरणों की कल्पना की जा सकती है जिनमें मालिक के अलावा किसी अन्य व्यक्ति की अधिग्रहण की कार्यवाही को विफल करने में रूचि हो सकती है। एक बार स्थगन आदेश प्राप्त हो जाने के बाद और सरकार और कलेक्टर को घोषणा के अनुसार कोई भी आगे की कार्रवाई करने से रोक दिया जाता है, तो उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। देरी के लिए और इसलिए वह अवधि जिसके दौरान स्थगन आदेश लागू होता है, को बाहर रखा जाना चाहिए। एक तरह से, स्थगन आदेश का क्रियान्वयन अधिग्रहण की कार्यवाही में आगे कदम उठाने में देरी का औचित्य प्रदान करता है जिसके लिए अधिकारी दोषी नहीं है।

16. उपरोक्त निर्णय में निर्धारित सिद्धांतों को इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का पालन करते हुए, जिसके साथ हम सम्मानजनक समझौते में है, इसलिए, हमारा विचार है कि राज्य/प्रतिवादी यहां पहले उल्लेखित अवधि को बाहर करने का हकदार था। और यह भी माना जाना

चाहिए कि यदि ऐसी अवधि को हटा दिया जाता है तो पुरस्कार पारित होने से पहले अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा की तारीख से दो साल की अवधि समाप्त नहीं होगी और तदनुसार, संपूर्ण अधिग्रहण कार्वाही को रोकने का प्रश्न चूक हो ही नहीं सकती।

17. इससे पहले कि हम इस फैसले से अलग हो, हम इस न्यायालय के फैसले से निपट सकते है जैसा कि अशोक कुमार मामले में अपीकर्ताओं के लिए वरिष्ठ एफ वकील ने भरोसा किया था (सुप्रा) हमारे विचार में, यह निर्णय एक अलग स्तर पर है। उस निर्णय में, यह सच है कि निषेधाज्ञा का अंतरिम आदेश पारित किया गया था, लेकिन बढाया नहीं गया था, जबकि वर्तमान मामले में माना जाता है कि अंतरिम आदेश जो अदालत द्वारा दिया गया था एक आदेश द्वारा सीमित अवधि को अगले आदेश तक पढा दिया गया। दिनांक 03 जुलाई, 1991 जो राज्य/प्रतिवादियों द्वारा दायर स्थगन आदेश को हटाने के लिए आवेदन पर पारित किया गया था। ऐसी स्थिति होने पर और यहां उपर की गई हमारी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं में मामले के लंबित रहने के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का लाभ उठाया है। जिस रिट याचिका में राज्य/उत्तरदाताओं द्वारा स्थगन आदेश को हटाने के लिए एक आवेदन दायर करके इसे रद्द करने की मांग की गई थी, यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो साल के भीतर अनुदान पारित किया गया था। और उत्तरदाता 11 फरवरी, 1988

से 3 जुलाई, 1991 तक की अवधि को बाहर करने के हकदार थे और इसलिए, यदि इस अवधि को अधिनियम की धारा 11ए के स्पष्टीकरण में निहित के रूप में बाहर रखा गया है, तो अनुदान समय के भीतर था और इसलिए, यह मानने का प्रश्न कि उक्त अवधि की समाप्ति के कारण अधिग्रहण की कार्यवाही समाप्त हो जानी चाहिए। उत्पन्न ही नहीं हो सकता, पक्षकारों के विद्वान वकील द्वारा कोई अन्य दलील नहीं दी गई।

18. उपरोक्त कारणों से, हमें उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता है और तदनुसार अपील खारिज कर दी जाती है। लागत के रूप में कोई ऑर्डर नहीं होगा।

अपील अस्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी देवांगिनी औदिच्य (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।